**श्री जुएल उरांवः** सर, malnutrition से उबरने के लिए उनको अच्छा खाना दिया जाए, इसके लिए हम लोग उनको डायरेक्शन देते हैं। दूसरा यह है कि ट्राइबल इलाकों में मैथेमेटिक्स और अंग्रेजी की पढ़ाई कम है। उसके लिए भी अगर वहां की राज्य सरकार हमसे कोचिंग के लिए एक्स्ट्रा गांट मांगेगी, तो उसको देने का भी प्रावधान है। नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अभी जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शुरू किया गया है, इसके कारण जो वेकेंसी रहती थी, वह अब धीरे-धीरे कम होती जा रही है। वेकेंसीज़ कम हैं, थोड़ी फिल अप नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी पहले जितना गैप था, उससे अभी कम हुआ है।

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: The State Government and the Central Government are the same. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: That is over now. ...(*Interruptions*)...

**श्री मधुसूदन मिस्त्रीः** सिर्फ, पैसा देना ही ट्राइबल मिनिस्ट्री का काम नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री सभापतिः** वह अलग बात है। That is the different matter. ...(*Interruptions*)... You can take it up later on and have a more detailed discussion. Mr. Mistryji, please. Shri Ram Nath Thakur.

**श्री राम नाथ ठाकुरः** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 में कितने स्कूलों का मंत्री जी या इनके पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया है और जो कमियां हैं, उनको पूरा करने के बारे में अभी तक इनके पास क्या रिपोर्ट हैं?

**श्री जुएल उरांवः** सर, इसकी रिपोर्ट अभी मेरे पास नहीं है। मैं माननीय सदस्य को इसके बारे में लिखित रूप में जानकारी दे दूंगा।

**श्री सभापतिः** ये आपको जानकारी दे देंगे। Thank you. ...(**व्यवधान**)...

**श्री नीरज शेखरः** मंत्री जी, क्या आपने निरीक्षण किया है? ...(**व्यवधान**)...

**श्री जुएल उरांवः** हां, किया है। ...(**व्यवधान**)...

**श्री नीरज शेखरः** क्या आपने निरीक्षण किया है? ...(**व्यवधान**)...

**श्री जुएल उरांवः** निरीक्षण हुआ है। ...(**व्यवधान**)... उसकी जानकारी मैं लिखित रूप में दे दूंगा।

**Registration of persons convicted of sexual offences**

*32. DR. K. P. RAMALINGAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has proposed in its draft guidelines for registration of sex offenders, inclusion of all those convicted for sexual offences ranging from voyeurism and stalking to rape and aggravated sexual assault;

(b) whether it is also a fact that registration will be made only for offenders of the age of 18 years and above;

(c) whether according to the said draft guidelines, those convicted of sexual offences will be obliged to provide all prescribed information which may include name, address, telephone number, passport number, etc.; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HARIBHAI PARTHIBHAI CHAUDHARY): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

***Statement***

(a) and (b) Draft guidelines on the proposal to set up Sex Offenders Registry in India is under preparation in consultation with relevant Ministries/organizations, before they are put out for wider consultation with the State Governments and the public. The initial consultation draft includes the registration of individuals convicted for offences like rape, voyeurism, stalking and aggravated sexual assault and includes possibility of registration of offenders below and above 18 years.

(c) and (d) According to draft guidelines proposed, extensive information on the offender will be collected. This will include, *inter-alia*, name and aliases – registration of primary or given name, nicknames, pseudonyms, Interact identifiers and addresses, telephone numbers, addresses including temporary lodging information, travel and immigration documents, employment information, professional licenses, school/college/ institute information, vehicle information, date of birth, criminal history, current photograph, fingerprints and palm prints, DNA sample, driver's license, identification card, PAN card number, AADHAR card number and voter ID No.

DR. K. P. RAMALINGAM: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has stated in his written reply that draft guidelines on the proposal to set up Sex Offenders Registry in India is under preparation. I am happy that the Government is preparing a registration of sexual offenders. Sir, unless found guilty we cannot say anyone as offender. So, my question is whether the proposed registration or data base of sexual offenders would be prepared on the basis of FIR or charge sheet or conviction. The proposed registration solely should be on the basis of conviction because unless found guilty, we can't tarnish the image of anyone. So, I would like to know from the hon. Home Minister on what basis the registration or data base of the sexual offenders would be prepared.

**श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः** सभापति महोदय, माननीय सांसद ने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है और यह ड्राफ्ट बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पर है। अभी इसकी जो रजिस्ट्री प्रक्रिया है, वह पुलिस स्टेशन में जो एफ.आई.आर दर्ज करते हैं, उसके आधार पर है। हमने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, वह अभी प्राइमरी स्टेज पर है। हमने यह ड्राफ्ट सभी मिनिस्ट्रीज को भेजा है, लॉ मिनिस्ट्री को भेजा है, सी.बी.आई को भेजा है। उसके बाद हम लोग स्टेट को भी भेजेंगे तथा पब्लिक में भी

[श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी]
भेजेंगे। मैं आपका भी सुझाव लेना चाहूंगा तथा पूरे सदन का भी इसमें सुझाव लेना है, क्योंकि यह अभी प्राइमरी स्टेज पर है। उसमें हमने प्रावधान किया है कि सजा कम्पलीट होने पर छः दिन के बाद उसका नाम इसमें डालेंगे।

DR. K. P. RAMALINGAM: Sir, my second question is this. All over the world, sexual offenders were kept under surveillance. In countries like the US, they have a public website on sex offenders. I came to know that the Government is also thinking of coming out with an online database that will be accessible to the public through a citizen portal, through the Crime and Criminal Tracking Network and System. I would like to know by when this portal would become operational.

**श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः** सभापति महोदय, पहले तो मैं आपको बताऊं कि यह बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पर है। हमने अमेरिका, यू.एस.ए., कनाडा, जर्मनी इन सभी देशों की डिलेटल्स मंगवाई हैं। इन लोगों ने रजिस्ट्री का प्रावधान किया है किन्तु फिर भी अपराध कम नहीं हुए। उसमें जो कमी होगी, वह भी इसमें डालेंगे। हम सभी सदस्यों के सुझाव लेंगे। अभी यह बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पर है। आपने जो स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है, उस पर हमने काम शुरू कर दिया है।

**श्रीमती रजनी पाटिलः** महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं कि जब अपराध होते हैं तथा महिलाएं उनको रजिस्टर करने के लिए जाती हैं, तो भी वहां पुलिस स्टेशन में बहुत सारे अपराध होते हैं। तो उसके लिए कोई वूमन-फ्रेंडली व्यवस्था आपने करने की सोची है?

**श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः** पहले से ही कानून 166(A) और 166(B) जिसमें हमने बताया कि कोई भी ऑफिसर एफ.आई.आर दर्ज करने से इंकार करता है तो उसमें छः महीने से लेकर दो साल की सजा का प्रावधान किया है।

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, the Supreme Court has already laid down certain guidelines about what sexual harassment is and has asked all the companies, establishments and, industries to publish those guidelines. I would like to ask the Minister whether the Government of India is monitoring this through the States. But, in my experience, wherever I have gone, I have not seen those Supreme Court guidelines being published in the establishments. I would like to know from the Minister what proposals they have to stop sexual harassment and to educate people about what sexual harassment is.

**श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः** सभापति महोदय, गृह मंत्रालय बार-बार स्टेट्स को एडवाइज़री जारी करता है। लास्ट में जनवरी, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, उसके बारे में हम बार-बार स्टेट्स जारी करते रहते हैं। वैसे तो लॉ एंड आर्डर स्टेट का विषय है, फिर भी हम बार-बार स्टेट्स को गाइडलाइंस देते ही रहते हैं।

SHRI T. K. RANGARAJAN: No, Sir. This is not correct. When the Supreme Court guidelines are not implemented, what directions do you give to the State Governments?

MR. CHAIRMAN: Please sit down.

**श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरीः** यह प्रश्न स्पेसिफिक है। इसके साथ कुछ जोड़ें तो वह अलग है।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, there is a clear direction of the Supreme Court to constitute a committee on sexual harassment at every workplace. I can assert that more than 90 per cent of the workplaces in our country do not have sexual harassment committees, as directed by the Supreme Court. Please come up specifically about what the Home Ministry is doing. ...(*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: Sir, even the public sector and Government establishments are supposed to have these committees.

MR. CHAIRMAN: You have a point. Let that be taken note of. Yes, Mantri*ji*. ...(*Interruptions*)... One minute. ...(*Interruptions*)...

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, on sexual harassment, the Home Minister should tell us… ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister. ...(*Interruptions*)... The Home Minister is speaking. Please. ...(*Interruptions*)...

**गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)ः** सभापति महोदय, sexual harassment को रोकने के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट से समय-समय पर गाइडलाइन्स जारी की जाती हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी श्री हरिभाई पार्थीपाई चौधरी ने बताया कि इस संबंध में सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा बराबर गाइडलाइन्स जारी की जाती हैं और ऐसी गाइडलाइन्स जारी की गई हैं। जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, इस संबंध में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी तक यह initial stage में है। अभी एक ड्राफ्ट गाइडलाइन्स तैयार हुई हैं। इसको मिनिस्ट्रीज जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, सीबीआई आदि को उनके कमेंट्स के लिए भेजा गया है। उनके कमेंट्स प्राप्त हो जाने के बाद फिर हम उसको पब्लिक डोमेन में डालेंगे और इस संबंध में आम पब्लिक का भी सुझाव लेंगे।

**श्री सभापतिः** ठीक है।

**श्री राजनाथ सिंहः** सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन sexual harassment को रोकने के लिए **...(व्यवधान)...**

SHRI TAPAN KUMAR SEN : Hon. Supreme Court has already given a direction to act. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No, no; please. ...(*Interruptions*)... This is not a discussion. ...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN : When there is already a certain direction ...(*Interruptions*)... you think that okay, it will take some time to come into effect. But when there is already a certain direction, which is the part of the law of our land to be implemented and that has not been implemented during the span of last three years, please ascertain it. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No, no; please. ...(*Interruptions*)... Mr. Rangarajan, let me clarify one thing. What is the question? The question is about proposed guidelines. So, please direct your supplementaries to the proposed guidelines and not to the wider directive which everybody knows exists. ...(*Interruptions*)...

SHRI T. K. RANGARAJAN: When there is a Supreme Court guideline to form a Committee, even a public sector or Central Government undertaking doesn't obey that. That is the point. If there is another guideline, nothing will happen in this country. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Fine. Thank you.

**Criteria for inclusion of languages in eighth schedule**

*33. SHRI VIJAY GOEL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the reasons for not having adopted a fixed criterion for inclusion of languages in the Eighth Schedule of Constitution of India;

(b) on what basis does Government decipher between a dialect of a language and a new language before granting a language status;

(c) the names of the languages which have been included in the Eighth Schedule of the Constitution so far, State-wise; and

(d) the details of benefits a language avails after its inclusion in the Eighth Schedule?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

***Statement***

(a) and (b) "Language" is a socio-cultural-geographical construct in the sense that all languages begin as dialects/varieties/mother tongues but due to various socio-economic-political reasons one of the varieties of any language develops into or acquires the status of a standard variety; "language" may thus be defined as the standard variety, so that mother tongue of those speaking related varieties may be deemed to be the standard variety. Thus, Awadhi, Braj Bhasha and Khadi Boli constitute what is known as Hindi today and Hindi may, therefore, be considered the mother tongue/standard language for these varieties.

There are no linguistic criteria for differentiating between a language and a dialect. Socially, a dialect may gradually evolve into a language and acquire the status of a language.